

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन और चुनौतियाँ

\*<sup>1</sup>सत्य नरायन यादव, <sup>2</sup>डॉ. निलेश कुमार पटेल और <sup>3</sup>डॉ. धाराश्री श्रीवास

<sup>1</sup>सहायक प्राध्यापक, स्व. गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरावां (खरगोन), मध्य प्रदेश, भारत।

<sup>2</sup>प्राचार्य, स्व. गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरावां (खरगोन), मध्य प्रदेश, भारत।

<sup>3</sup>सहायक प्राध्यापिका, स्व. गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरावां (खरगोन), मध्य प्रदेश, भारत।

### Article Info.

E-ISSN: 2583-6528

Impact Factor (QJIF): 8.4

Peer Reviewed Journal

Available online:

[www.alladvancejournal.com](http://www.alladvancejournal.com)

Received: 09/March/2026

Accepted: 16/April/2026

### सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शैक्षिक रूपरेखा में एक युगांतरकारी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल से चली आ रही शिक्षा पद्धति को आधुनिक, लचीला और कौशल-आधारित बनाना है। यह नीति 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्षों बाद आई है, जो 'पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही' के पांच मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। स्कूली स्तर पर, यह 10+2 के पुराने ढांचे को 5+3+3+4 के नए शैक्षणिक डिजाइन में बदलती है, जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखता है। इसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE) को औपचारिक स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है, जिससे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यह नीति रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर अनुभवात्मक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करती है, साथ ही कक्षा 6 से ही व्यावसायिक कौशल और कोडिंग की शुरुआत करके छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, NEP 2020 'मल्टीपल एंटी और एग्जिट' विकल्पों के साथ चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम की शुरुआत करती है, जो छात्रों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा जारी रखने या बदलने की स्वतंत्रता देता है। 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' की स्थापना और एक एकल नियामक निकाय (HECI) का गठन प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त, शोध संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि, नीति के सफल निष्पादन में जीडीपी का 6% निवेश सुनिश्चित करना, ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटना और शिक्षकों का व्यापक प्रशिक्षण करना प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। अंततः, यह नीति भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में पुनर्जीवित करने का एक व्यापक विजन प्रस्तुत करती है, जो छात्रों को न केवल रोजगार के लिए बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के लिए भी तैयार करती है।

### \*Corresponding Author

सत्य नरायन यादव

सहायक प्राध्यापक, स्व. गुलाब बाई यादव  
स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरावां (खरगोन),  
मध्य प्रदेश, भारत।

**मुख्य शब्द:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन, 5+3+3+4 संरचना, सकारात्मक पक्ष, चुनौतियाँ।

### 1. प्रस्तावना:

किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी भावी पीढ़ी का चरित्र निर्माण उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। भारत, जो अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा और 'विश्व गुरु' की छवि के लिए जाना जाता रहा है, लंबे समय से एक ऐसी शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहा था जो व्यापक रूप से औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित थी। 21वीं सदी की

तीव्र बदलती वैश्विक परिस्थितियों, तकनीकी नवाचारों और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) की घोषणा की गई। यह नीति 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेती है, जो पिछले 34 वर्षों से

प्रचलन में थी। डॉ. के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया यह दस्तावेज न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि यह भारतीय शिक्षा को 'रटने' की संस्कृति से मुक्त कर 'सीखने' की कला की ओर ले जाने का एक दूरदर्शी प्रयास है।

NEP 2020 का मुख्य दर्शन भारत को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलना है। यह नीति इस विचार पर बल देती है कि शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित न रहकर व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास का साधन बननी चाहिए। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के ढांचे को अधिक लचीला, बहुविषयक (Multidisciplinary) और समावेशी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ एक ओर यह नीति वैश्विक मानकों को अपनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर यह भारतीय मूल्यों, भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण पर भी समान जोर देती है। यह शोध पत्र इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि यह नीति के प्रमुख स्तंभों, जैसे कि 5+3+3+4 संरचना, डिजिटल साक्षरता, और उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह उन चुनौतियों की भी पड़ताल करता है जो इस महत्वाकांक्षी विजन को धरातल पर उतारने के मार्ग में बाधा बन सकती हैं। संक्षेप में, यह प्रस्तावना उस वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है जिसके आधार पर भारत अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और भविष्योन्मुखी बनाने की ओर अग्रसर है।

## 2. शोध के उद्देश्य

- NEP 2020 की प्रमुख विशेषताओं को समझना।
- स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के नए ढांचे का विश्लेषण करना।
- नीति के कार्यान्वयन (Implementation) में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

## 3. शोध विधि

यह शोध मुख्य रूप से वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है। इसमें नीति के मौजूदा दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है और उनके संभावित सामाजिक-शैक्षिक प्रभावों की व्याख्या की गई है।

## 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की मुख्य विशेषताएं भारतीय शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बदलने का लक्ष्य रखती हैं। इन विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तृत रूप से समझा जा सकता है:

- स्कूली शिक्षा का नया ढांचा (5+3+3+4 संरचना):** सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पारंपरिक 10+2 ढांचे को समाप्त कर उसे 5+3+3+4 के प्रारूप में बदलना है। इसमें प्रथम 5 वर्ष 'फाउंडेशनल स्टेज' (आंगनवाड़ी और कक्षा 1-2) के होंगे, जहाँ बच्चों की नींव खेल-कूद और गतिविधि आधारित शिक्षण से मजबूत की जाएगी। इसके बाद 3 वर्ष 'प्रिपरेटरी' (कक्षा 3-5), 3 वर्ष 'मिडिल' (कक्षा 6-8) और अंतिम 4 वर्ष 'सेकेंडरी' स्टेज (कक्षा 9-12) के होंगे। यह नया ढांचा 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाता है।
- बहुभाषावाद और मातृभाषा पर जोर:** नीति का एक प्रमुख आकर्षण कम से कम कक्षा 5 तक (संभव हो तो कक्षा 8 तक) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में रखना है। शोध बताते हैं कि बच्चे अपनी मूल भाषा में अवधारणाओं को अधिक तेजी से और बेहतर ढंग से समझते हैं। इसके साथ ही, स्कूलों में 'त्रि-भाषा फॉर्मूला' लागू किया जाएगा, जिसमें छात्रों को अपनी पसंद की भारतीय भाषाएं सीखने की स्वतंत्रता होगी।

- कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा:** शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) और कोडिंग की शुरुआत की जाएगी। छात्रों को इंटरशिप के अवसर दिए जाएंगे ताकि वे स्थानीय शिल्पकारों या तकनीकी विशेषज्ञों के साथ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह कदम किताबी ज्ञान और वास्तविक कौशल के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास है।

- उच्च शिक्षा में लचीलापन (Multiple Entry and Exit):** उच्च शिक्षा में अब छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई छोड़ और फिर से शुरू कर सकते हैं। एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर 'प्रमाण पत्र', दो वर्ष पर 'डिप्लोमा', तीन वर्ष पर 'डिग्री' और चार वर्ष पर 'शोध के साथ डिग्री' का प्रावधान है। छात्रों के क्रेडिट को सुरक्षित रखने के लिए एक 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC) बनाया जाएगा, जिससे संस्थान बदलने पर भी उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

- मूल्यांकन पद्धति में बदलाव:** रिपोर्ट कार्ड अब केवल अंकों का विवरण नहीं होगा, बल्कि यह छात्र के 360-डिग्री समग्र मूल्यांकन (Holistic Progress Report) पर आधारित होगा। इसमें छात्र का स्वयं का मूल्यांकन, सहपाठियों का मूल्यांकन और शिक्षक का मूल्यांकन शामिल होगा। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम करते हुए उन्हें ज्ञान के अनुप्रयोग पर केंद्रित किया जाएगा।

- शोध और डिजिटल शिक्षा:** देश में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (NRF) की स्थापना की जाएगी। साथ ही, शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल माध्यमों के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है ताकि सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाई जा सके।

यह विशेषताएं सामूहिक रूप से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करती हैं जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होने के साथ-साथ भारतीय जड़ों से भी जुड़ी हुई है।

## 5. महत्वपूर्ण विश्लेषण: 5+3+3+4 संरचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे क्रांतिकारी विशेषता इसकी नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना है। पारंपरिक 10+2 प्रणाली, जो पिछले कई दशकों से भारतीय शिक्षा का आधार थी, उसे अब 5+3+3+4 संरचना से बदल दिया गया है। यह बदलाव केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development) के चरणों पर आधारित एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।

नीचे इस संरचना का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है:

### i). फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage): 5 वर्ष

यह चरण बच्चों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती वर्षों को कवर करता है।

- **आयु वर्ग:** 3 से 8 वर्ष।
- **विभाजन:** 3 साल की प्री-स्कूलिंग (आंगनवाड़ी/बालवाटिका) और 2 साल की प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 और 2)।
- **विशेषता:** यहाँ कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होगी। शिक्षा पूरी तरह से खेल-कूद, पहलियों और गतिविधि आधारित शिक्षण (Activity-based learning) पर केंद्रित होगी। इसका उद्देश्य बच्चे के भीतर सीखने की जिज्ञासा और बुनियादी साक्षरता विकसित करना है।

### ii). प्रिपरेटरी स्टेज (Preparatory Stage): 3 वर्ष

यह चरण बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है।

- **आयु वर्ग:** 8 से 11 वर्ष (कक्षा 3 से 5)।
- **विशेषता:** यहाँ से हल्के विषयों (भाषा, गणित, विज्ञान, कला) का परिचय दिया जाएगा। शिक्षण पद्धति अभी भी संवादात्मक (Interactive) रहेगी, लेकिन छात्रों को धीरे-धीरे रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने की ओर मोड़ा जाएगा।

### iii). मिडिल स्टेज (Middle Stage): 3 वर्ष

यह चरण छात्रों के लिए विषयों के गहन अध्ययन की शुरुआत है।

- **आयु वर्ग:** 11 से 14 वर्ष (कक्षा 6 से 8)।
- **विशेषता:** इस स्तर पर विषयों का एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) और कोडिंग की शुरुआत है। कक्षा 6 से ही छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से व्यावहारिक कौशल (जैसे बर्दईगिरी, बागवानी, बिजली का काम आदि) सीखने का अवसर मिलेगा।

### iv). सेकेंडरी स्टेज (Secondary Stage): 4 वर्ष

यह चरण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो छात्र के करियर की दिशा तय करता है।

- **आयु वर्ग:** 14 से 18 वर्ष (कक्षा 9 से 12)।
- **विशेषता:** यहाँ सबसे बड़ा बदलाव 'स्ट्रीम सिस्टम' (Science, Commerce, Arts) का खात्मा है। छात्र अब बहुविषयक (Multidisciplinary) तरीके से विषयों का चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिकी पढ़ने वाला छात्र अपनी रुचि के अनुसार इतिहास या संगीत भी पढ़ सकता है। परीक्षाओं को अधिक विश्लेषणात्मक बनाया जाएगा ताकि केवल परीक्षा के समय पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो सके।

**तालिका 1:** तुलनात्मक विश्लेषण: पुरानी बनाम नई संरचना

मापदंड	पुरानी संरचना (10+2)	नई संरचना (5+3+3+4)
प्रवेश आयु	6 वर्ष से शुरू	3 वर्ष से शुरू (आंगनवाड़ी शामिल)
शिक्षण पद्धति	रटने और पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित	खेल, गतिविधि और कौशल पर केंद्रित
विषयों का चुनाव	कक्षा 11 से कठोर स्ट्रीम सिस्टम	कक्षा 9 से लचीलापन और बहुविषयक विकल्प
व्यावसायिक शिक्षा	उच्च शिक्षा या कॉलेज स्तर पर	कक्षा 6 से ही प्रारंभ

### 6. लाभ और सकारात्मक पक्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के लाभ और सकारात्मक पक्ष अत्यंत व्यापक हैं, जो भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- समग्र और बहुमुखी विकास (Holistic Development):** NEP 2020 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शिक्षा को केवल 'अंकों' तक सीमित न रखकर छात्र के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित करती है। 5+3+3+4 संरचना के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की देखभाल (ECCE) पर ध्यान दिया गया है, जिससे बच्चों की नींव मजबूत होगी। 360-डिग्री रिपोर्ट कार्ड छात्रों के व्यवहार, कौशल और मानसिक क्षमताओं का समग्र चित्रण प्रस्तुत करेगा।
- रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति:** यह नीति शिक्षा में 'क्या सोचना है' के बजाय 'कैसे सोचना है' (How to think) पर बल देती है। बोर्ड परीक्षाओं के बोझ को कम करना और विषयों के चुनाव में लचीलापन प्रदान करना छात्रों को रटने के तनाव से मुक्त

करेगा। अब विज्ञान का छात्र संगीत पढ़ सकेगा और कला का छात्र भौतिकी, जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

- कौशल विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता:** कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटरनेट को अनिवार्य करना एक क्रांतिकारी कदम है। इससे छात्र स्कूल से निकलते समय किसी न किसी हुनर में दक्ष होंगे, जो भविष्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को सफल बनाने में सहायक होगा।
- उच्च शिक्षा में वैश्विक मानक और लचीलापन:** उच्च शिक्षा में 'मल्टीपल एंट्री और एग्जिट' की सुविधा उन छात्रों के लिए वरदान है जो आर्थिक या व्यक्तिगत कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। अब उनका साल बर्बाद नहीं होगा और उन्हें उनके द्वारा पूरे किए गए समय के आधार पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलने से भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देश में ही मिल सकेगी।
- समावेशिता और डिजिटल साक्षरता:** यह नीति 'जेंडर इंकलूजन फंड' और विशेष शिक्षा क्षेत्रों (SEZ) के माध्यम से वंचित समूहों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करती है। साथ ही, शिक्षा में तकनीक और AI के एकीकरण से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।

NEP 2020 भारतीय युवाओं को 21वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का एक सशक्त माध्यम है, जो भारत को पुनः 'विश्व गुरु' के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

### 7. कार्यान्वयन की चुनौतियां

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) कागजी तौर पर अत्यंत प्रगतिशील और दूरदर्शी प्रतीत होती है, किंतु भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में इसे धरातल पर उतारना एक अत्यंत जटिल कार्य है। इसके कार्यान्वयन (Implementation) के मार्ग में कई गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान किए बिना इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव होगा।

- वित्तीय संसाधन और बजट की कमी:** नीति में यह प्रस्ताव दिया गया है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी (GDP) के 6% तक बढ़ाया जाए। ऐतिहासिक रूप से, भारत में शिक्षा पर खर्च हमेशा 3% से 4% के आसपास रहा है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, शिक्षा बजट में इतनी भारी वृद्धि करना सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती है। पर्याप्त धन के अभाव में स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारना और नई तकनीक लाना कठिन होगा।
- डिजिटल डिवाइड (डिजिटल विभाजन):** NEP 2020 ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल साक्षरता पर बहुत अधिक जोर देती है। लेकिन भारत की वास्तविकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और बिजली की निरंतर आपूर्ति अभी भी एक समस्या है। अमीर और गरीब छात्रों के बीच मौजूद यह 'डिजिटल डिवाइड' शिक्षा में असमानता पैदा कर सकता है। सभी छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** यह नीति रटने के बजाय सोचने और कौशल आधारित शिक्षा की वकालत करती है। इसके लिए वर्तमान शिक्षकों के दृष्टिकोण और पढ़ाने के तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लाखों शिक्षकों को नई 5+3+3+4 संरचना, कोडिंग और व्यावसायिक विषयों के लिए प्रशिक्षित करना एक विशाल कार्य है। जब तक शिक्षक स्वयं इस नीति के दर्शन को नहीं समझेंगे, तब तक छात्रों तक इसका लाभ नहीं पहुँचेगा।

- iv). **भाषा संबंधी बाधाएं:** कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का विचार प्रशंसनीय है, लेकिन इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, जहाँ एक ही कक्षा में विभिन्न राज्यों के छात्र होते हैं, वहाँ किसी एक क्षेत्रीय भाषा को चुनना कठिन होगा। इसके अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री का अभाव भी एक बड़ी रुकावट है।
- v). **केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय:** भारत में शिक्षा एक 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) का विषय है, जिसका अर्थ है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चूंकि शिक्षा का वास्तविक क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद नीति के कार्यान्वयन की गति को धीमा कर सकते हैं।
- vi). **मूल्यांकन पद्धति में बदलाव:** पुरानी 'अंक-आधारित' प्रणाली से 'कौशल-आधारित' 360-डिग्री मूल्यांकन की ओर बढ़ना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए स्कूलों को नई मूल्यांकन प्रणालियों और डेटा प्रबंधन उपकरणों से लैस करना होगा, जो वर्तमान में कई सरकारी स्कूलों के लिए एक दूर का सपना है।

NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए निरंतर निगरानी, भारी निवेश और समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया, तो यह नीति केवल एक सुंदर दस्तावेज बनकर रह जाएगी।

### निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक दस्तावेजी सुधार नहीं है, बल्कि यह भारत की भावी पीढ़ी के बौद्धिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का एक व्यापक 'ब्लूप्रिंट' है। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई यह नीति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसर पिछली शताब्दी से बिल्कुल भिन्न हैं। शोध के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि नीति का मुख्य बल 'रटने वाली शिक्षा' (Rote Learning) के स्थान पर 'सीखने की प्रक्रिया' (Learning how to learn) पर है। यह बदलाव भारत को एक ऐसे समाज की ओर ले जाने का प्रयास है जहाँ ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह न होकर नवाचार और समस्या-समाधान का उपकरण बने।

नीति की सबसे बड़ी सफलता इस बात में निहित है कि यह शिक्षा को प्रारंभिक बाल्यावस्था (3 वर्ष की आयु) से जोड़ती है। 5+3+3+4 संरचना के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को मानव मस्तिष्क के विकास के वैज्ञानिक चरणों के अनुरूप ढाला गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में 'मल्टीपल एंट्री और एग्जिट' और 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' जैसे सुधार छात्रों को वह लचीलापन प्रदान करते हैं, जिसकी आज के गतिशील युग में नितांत आवश्यकता है। यह नीति भारतीय भाषाओं के गौरव को पुनर्स्थापित करने और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल करने का जो साहस दिखाती है, वह 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है।

हालाँकि, किसी भी नीति की महानता उसके इरादों में नहीं, बल्कि उसके 'कार्यान्वयन' (Implementation) में छिपी होती है। शोध के दौरान यह उभर कर आया है कि जीडीपी का 6% खर्च करने की प्रतिबद्धता, शिक्षकों का आधुनिक प्रशिक्षण और ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटना ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार को अत्यधिक सावधानी और गति के साथ काम करना होगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) का होना अनिवार्य है, ताकि नीति के लाभ अंतिम छोर पर खड़े छात्र तक पहुँच सकें।

अंततः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए आधुनिकता की ओर ले जाने का एक संतुलित प्रयास है। यह 'विश्व गुरु' के रूप में भारत की ऐतिहासिक पहचान को पुनः प्राप्त करने का एक आधुनिक मार्ग प्रशस्त करती है। यदि इस नीति को इसकी मूल भावना के साथ लागू किया जाता है, तो यह न केवल बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि एक ऐसे जागरूक, नैतिक और कौशल-संपन्न कार्यबल का निर्माण करेगी जो वैश्विक पटल पर भारत का नेतृत्व कर सके। यह नीति केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और नीति-निर्माताओं के लिए भी अपनी सोच बदलने का एक अवसर है। निष्कर्षतः, NEP 2020 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक 'क्रांतिकारी प्रस्थान बिंदु' (Turning Point) है, जो भारत की नियति को बदलने की क्षमता रखती है।

### संदर्भ सूची:

1. Aithal PS, Aithal S. Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMSTS)*. 2020;5(2):190-225.
2. उच्च शिक्षा विभाग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार; 2020. [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/NEP\\_Final\\_Hindi\\_0.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi_0.pdf)
3. Chauhan PS. National Education Policy 2020: A step towards transforming Indian education system. *Journal of Education and Practice*. 2020;11(24):115-119.
4. Jha P, Parvati P. National Education Policy 2020: A review of the fundamental issues. *Economic and Political Weekly*. 2020;55(34):12-15.
5. कस्तूरीरंगन के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार; 2019.
6. Kumar A. New Education Policy 2020: A comparative analysis with 1986 policy. *Indian Journal of Educational Research*. 2021;12(1):45-58.
7. Ministry of Education. National Education Policy 2020. Government of India; 2020. [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/NEP\\_Final\\_English\\_0.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)
8. एन.सी.ई.आर.टी.। बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद; 2022.
9. Panigrahi MR. National Education Policy 2020: A roadmap for school education. *Educational World Press*; 2020.
10. पचौरी जी। भारत की नई शिक्षा नीति: विजन और क्रियान्वयन। शिक्षा प्रकाशन; 2021.
11. Rao SS. Language policy and NEP 2020: Multilingualism in Indian classrooms. *Linguistic Journal of India*. 2021;15(2):88-102.
12. राजपूत जेएस। शिक्षा नीति और भारत का भविष्य। दैनिक जागरण। 2020 अगस्त 3.
13. Sahoo S, Sahu K. Vocational education in NEP 2020: A critical analysis. *Journal of Vocational Studies*. 2021;9(1):104-118.
14. त्यागी एस। नई शिक्षा नीति 2020: एक विश्लेषण। कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका)। 2020;68(11):5-10.
15. Tilak JBG. National Education Policy 2020: An overview. *Social Change*. 2020;50(4):597-605.